गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 279
दि. 10.02.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

मतदाता सूची की शुचिता पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी नजर, बंगाल एसआईआर पर सख्त

जीएनएस)। नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर उठा विवाद अब देश की सर्वोच्च अदालत के केंद्र में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाते हुए न केवल निर्वाचन आयोग को राहत देते हुए समयसीमा बढ़ाई, बल्कि प्रक्रिया में बाधा डालने वालों को स्पष्ट चेतावनी भी दी। अदालत ने यह साफ कर दिया कि लोकतंत्र की नींव मानी जाने वाली मतदाता सूची की शुद्धता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही या अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर विस्तार से सुनवाई की। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजरिया भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण में अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, क्योंकि अब इसमें राज्य सरकार के अधिकारियों का एक नया समूह भी शामिल किया गया है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की डेडलाइन को 14 फरवरी से एक सप्ताह आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने से पहले सभी दस्तावेजों की निष्पक्ष और पूरी जांच जरूरी है, ताकि किसी भी योग्य मतदाता का नाम गलत तरीके से न कटे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि माइक्रो ऑब्जर्वर या राज्य सरकार के जिन अधिकारियों को इस प्रक्रिया में लगाया गया है, उनकी भूमिका केवल निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ की सहायता तक सीमित होगी। अंतिम फैसला पूरी तरह ईआरओ का ही रहेगा। अदालत ने माना कि नए अधिकारियों की तैनाती से दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से अधिक समय लगेगा, इसलिए ईआरओ को निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाना

उचित है। इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत भी दिया कि वह प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उठ रही चिंताओं पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कोर्ट अंतरिम निर्देश इसलिए जारी कर रही है ताकि पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ सके और किसी भी तरह का भ्रम या टकराव न रहे। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जिन 8,555 ग्रुप-बी अधिकारियों की सूची सौंपी गई है, वे सभी उसी दिन शाम पांच बजे तक जिला निर्वाचन अधिकारियों को रिपोर्ट करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग के पास यह अधिकार रहेगा कि वह मौजूदा ईआरओ और सहायक ईआरओ को बदले या योग्य पाए जाने पर अन्य अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करे।

इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट का रुख न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि न्यायिक अनुशासन को लेकर भी बेहद सख्त नजर आया। बहस के दौरान जब कई वरिष्ठ वकील एक साथ बोलने लगे और एक-दूसरे की बात काटने लगे, तो चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अदालत कोई बाजार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सुनवाई के दौरान अनुशासन और गरिमा बनाए रखना अनिवार्य है, वरना अदालत सख्त कदम उठाने से नहीं हिचकेगी। यह टिप्पणी उस समय और तीखी हो गई जब वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने हस्तक्षेप करते हुए एक याचिका पर सवाल उठाया। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने तल्ख लहजे में कहा कि यह अदालत है, न कि कोई सार्वजनिक मंच, जहां मनमर्जी से बोलना स्वीकार्य हो।

राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान और अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। दीवान ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने मैनपावर की कमी को दूर करने के लिए 8,500 से अधिक अधिकारियों की व्यवस्था कर ली है। इस पर चीफ जस्टिस ने निर्वाचन आयोग से सीधा सवाल किया कि क्या उसे इन अधिकारियों की सूची मिल गई है। आयोग के वकील ने जवाब दिया कि अभी तक उन्हें नामों की पूरी जानकारी नहीं मिली है। इस पर कोर्ट ने असंतोष जताते हुए कहा कि ऐसी प्रक्रियाओं में तालमेल बेहद जरूरी है।

सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पूर्व मुख्य सचिव और वर्तमान प्रधान सचिव मनोज पंत भी अदालत में मौजूद रहे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 292 ईआरओ, जो ग्रुप-ए यानी एसडीएम रैंक के अधिकारी हैं, उनके नाम भेज दिए गए हैं। इसके अलावा कुल 8,525 सहायक ईआरओ की सूची भी साझा की गई है, जिसमें 65 प्रतिशत ग्रुप-बी, 10 से 12 प्रतिशत ग्रुप-सी और शेष ग्रुप-ए अधिकारी शामिल हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने निर्वाचन आयोग को सलाह दी कि वह जरूरत पड़ने पर एईआरओ को बदलने पर भी विचार करे।

मामले का एक गंभीर पहलू तब सामने आया, जब निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने अपने नोटिस जला दिए। इस आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया और पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने साफ संकेत दिया कि कानून व्यवस्था से जुड़ा यह मामला केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा हमला है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

निर्वाचन आयोग की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह संदेश जाना चाहिए कि भारत का संविधान सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होता है। उन्होंने बताया कि आयोग ने पहले ही एक विस्तृत हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कई चिंताजनक तथ्यों का उल्लेख किया गया है। उनका कहना था कि एक संवैधानिक संस्था होने के नाते निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि वह शीर्ष अदालत के सामने पूरी सच्चाई रखे।

पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का रुख यही संकेत देता रहा कि वह पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए किसी भी स्तर पर सख्ती बरतने से पीछे नहीं हटेगी। एसआईआर की समयसीमा बढ़ाने के साथ-साथ अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि मतदाता सूची की प्रक्रिया में बाधा डालने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। यह आदेश न केवल बंगाल बल्कि देशभर के लिए एक संदेश है कि लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत रखने के लिए कानून और संस्थाओं की सर्वोच्चता पर कोई समझौता नहीं होगा।

गांधीधाम–आदीपुर रेलखंड पर चौहरीकरण कार्य के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के गांधीधाम–भुज सेक्शन में गांधीधाम–आदीपुर चौहरीकरण (Quadrupling) परियोजना के अंतर्गत गांधीधाम केबिन–आदीपुर स्टेशनों के बीच कमीशनिंग से संबंधित प्रस्तावित (TWO) कार्य के कारण 13 फरवरी 2026 तक कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।

अहमदाबाद मंडल के गांधीधाम–भुज सेक्शन में गांधीधाम केबिन और आदीपुर स्टेशनों के बीच चौहरीकरण (Quadrupling) कमीशनिंग का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना क्षेत्र में रेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चौहरीकरण से इस खंड की लाइन क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे ट्रेनों का परिचालन अधिक सुचारु, समयनिष्ठ और सुरक्षित बनेगा। साथ ही माल एवं यात्री यातायात का बेहतर प्रबंधन संभव होगा, जिससे क्षेत्रीय व्यापार, उद्योग और यात्रियों को लाभ पहुँचेगा।

अहमदाबाद मंडल द्वारा परियोजना को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह पहल भारतीय रेल की आधुनिक, तेज़ और विश्वसनीय रेल सेवाएँ प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

पूर्णतः रद्द ट्रेनें

1.ट्रेन संख्या 19405/19406 पालनपुर-गांधीधाम–पालनपुर एक्सप्रेस 13 फरवरी 2026 तक निरस्त रहेगी।

2.ट्रेन संख्या 12965 बांद्रा टर्मिनस–भुज एक्सप्रेस 10 फरवरी 2026 को निरस्त रहेगी।

3.ट्रेन संख्या 12960 भुज–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 09 फरवरी 2026 को निरस्त रहेगी।

4.ट्रेन संख्या 09415/09416 बांद्रा टर्मिनस-गांधीधाम–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 12 फरवरी 2026 को निरस्त रहेगी।

5.ट्रेन संख्या 22952 गांधीधाम–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 12 फरवरी 2026 को निरस्त रहेगी।

6.ट्रेन संख्या 22951 बांद्रा टर्मिनस–गांधीधाम एक्सप्रेस 13 फरवरी 2026 को निरस्त रहेगी।

7.ट्रेन संख्या 09010 भुज–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 09 फरवरी 2026 को निरस्त रहेंगी।

8.ट्रेन संख्या 09011 बांद्रा टर्मिनस–भुज स्पेशल 10 फरवरी 2026 को निरस्त रहेंगी।

9.ट्रेन संख्या 09012 भुज–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 11 फरवरी 2026 को निरस्त रहेंगी।

आंशिक निरस्त ट्रेनें

1.ट्रेन संख्या 20908 भुज-दादर सयाजी नगरी एक्सप्रेस 9 फरवरी 2026 को भुज-गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

2.ट्रेन संख्या 22955 बांद्रा टर्मिनस-भुज कच्छ एक्सप्रेस 9 फरवरी 2026 को गांधीधाम और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

3.ट्रेन संख्या 22956 भुज-बांद्रा टर्मिनस कच्छ एक्सप्रेस 10 फरवरी 2026 को भुज-गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

4.ट्रेन संख्या 14321/14311 बरेली–भुज एक्सप्रेस 09 फरवरी 2026 को गांधीधाम और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी तथा 10 और 11 फरवरी 2026 को सामाख्याली और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

5.ट्रेन संख्या 14322/14312 भुज–बरेली एक्सप्रेस 10 फरवरी 2026 को भुज-गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी तथा 11 और 12 फरवरी 2026 को भुज-सामाख्याली के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

6.ट्रेन संख्या 22903 बांद्रा टर्मिनस–भुज एसी एक्सप्रेस 11 फरवरी 2026 को अहमदाबाद और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

7.ट्रेन संख्या 16336 नागरकोइल–गांधीधाम एक्सप्रेस 10 फरवरी 2026 को अहमदाबाद और गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

8.ट्रेन संख्या 22904 भुज-बांद्रा टर्मिनस एसी एक्सप्रेस 9 फरवरी 2026 को भुज और गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी तथा 12 फरवरी 2026 को भुज और अहमदाबाद के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

9. ट्रेन संख्या 94801 अहमदाबाद–भुज नमोभारत एक्सप्रेस 10 फरवरी 2026 तक गांधीधाम और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी तथा 11 और 12 फरवरी 2026 को धांगध्रा और भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

10. ट्रेन संख्या 94802 भुज-अहमदाबाद नमोभारत एक्सप्रेस 11 फरवरी 2026 तक भुज और गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी तथा 12 और 13 फरवरी 2026 को भुज और धांगध्रा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

11. ट्रेन संख्या 20983 भुज–दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस 10 फरवरी 2026 को भुज-गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

12. ट्रेन संख्या 11092 पुणे-भुज एक्सप्रेस 09 फरवरी 2026 को गांधीधाम-भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

13. ट्रेन संख्या 11091 भुज–पुणे एक्सप्रेस 11 फरवरी 2026 को भुज-गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

14. ट्रेन संख्या 22483 भगत की कोठी–गांधीधाम एक्सप्रेस 10,11 और 12 फरवरी 2026 को भीलड़ी-गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

15. ट्रेन संख्या 22484 गांधीधाम-भगत की कोठी एक्सप्रेस 11,12 और 13 फरवरी 2026 को गांधीधाम-भीलड़ी के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

मार्ग परिवर्तित ट्रेनें

▸▸ ट्रेन संख्या 20907 दादर-भुज सयाजी नगरी एक्सप्रेस 9 और 10 फरवरी 2026 को परिवर्तित मार्ग वाया आदिपुर-गांधीधाम केबिन-भीमासर के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन गांधीधाम स्टेशन पर नहीं जाएगी।

▸▸ ट्रेन संख्या 22955 दादर-भुज सयाजी नगरी एक्सप्रेस 10 और 11 फरवरी 2026 को परिवर्तित मार्ग वाया भीमासर-गांधीधाम केबिन-आदिपुर के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन गांधीधाम स्टेशन पर नहीं जाएगी।

▸▸ ट्रेन संख्या 20908 भुज-दादर सयाजी नगरी एक्सप्रेस 10,11 और 12 फरवरी 2026 को परिवर्तित मार्ग वाया भीमासर-गांधीधाम केबिन-आदिपुर के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन गांधीधाम स्टेशन पर नहीं जाएगी।

▸▸ ट्रेन संख्या 22956 भुज-बांद्रा टर्मिनस कच्छ एक्सप्रेस 9,11 और 12 फरवरी 2026 को परिवर्तित मार्ग वाया आदिपुर-गांधीधाम केबिन-भीमासर के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन गांधीधाम स्टेशन पर नहीं जाएगी।

▸▸ ट्रेन संख्या 20984 दिल्ली सराय रोहिल्ला-भुज एक्सप्रेस 11 फरवरी 2026 को परिवर्तित मार्ग वाया भीमासर-गांधीधाम केबिन-आदिपुर के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन गांधीधाम स्टेशन पर नहीं जाएगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि उपरोक्त परिवर्तन को ध्यान में रखकर यात्रा करें। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

श्रीलंका के जनता विमुक्ति पेरामुना के महासचिव श्री टिल्विन सिल्वा एवं प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सुदृढ़ हुए भारत-श्रीलंका संबंधों को आगे बढ़ाने में फलदायी बैठक

▸▸ श्रीलंका पॉलिसी ड्रिवन स्टेट के रूप में गुजरात की विभिन्न नीतियों का लाभ लेकर रुचि वाले सहयोग क्षेत्रों में गुजरात के साथ सहभागीता कर सकता है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष श्रीलंका में आयोजित प्रदर्शनी के लिए देने पर महासचिव ने आभार व्यक्त किया

▸▸ गुजरात की एक्सपर्टीज – नॉलेज शेयरिंग और नॉ-हाउ का लाभ लेने की तत्परता व्यक्त की

वाइब्रेंट समिट 2027 में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री का आमंत्रण

जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से श्रीलंका के शासक दल जनता विमुक्ति पेरामुना के महासचिव श्री टिल्विन सिल्वा और प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री ने इस डेलिगेशन का गुजरात आगमन पर स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत और श्रीलंका के संबंध अधिक सुदृढ़ हुए हैं तथा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को और गति मिली है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बैठक इन संबंधों को और आगे बढ़ाने में फलदायी सिद्ध होगी।

उन्होंने कहा कि गुजरात एक पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों की नीतियों का लाभ श्रीलंका अपने रुचि वाले क्षेत्रों के लिए ले सकता है इसके लिए राज्य सरकार और श्रीलंका के बीच पारस्परिक समन्वय बढ़ाने की उन्होंने वकालत की।

इतना ही नहीं, इस बैठक में अधिक से अधिक गुजरातियों के श्रीलंका भ्रमण को बढ़ावा देने के लिए भी चर्चा-विमर्श किया गया।

जेवीपी के महासचिव ने भावना व्यक्त की कि महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भूमि गुजरात और भारत की उनकी यह पहली यात्रा है और इससे वे भावुक हुए हैं तथा गुजरात की प्रगति से प्रभावित हैं।

उन्होंने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष (रेलिक्स) श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित प्रदर्शनी के लिए गुजरात द्वारा उपलब्ध कराने पर केंद्र और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। श्री टिल्विन सिल्वा ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि आवश्यकता के समय भारत ने हमेशा श्रीलंका को इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग दिया है और उसके साथ खड़ा रहा है।

उन्होंने गुजरात-श्रीलंका के औद्योगिक क्षेत्र में भागीदारी के प्रति भी उत्कृष्टता दर्शाई तथा अमूल की अपनी यात्रा का उल्लेख करते हुए सहकारिता क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में गुजरात से एक्सपर्टीज, नॉलेज शेयरिंग और नॉ-हाउ प्राप्त करने में गहरी रुचि दिखाई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आगामी वाइब्रेंट समिट 2027 में श्रीलंका को पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया तथा प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य की क्षेत्रीय औद्योगिक क्षमताओं को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वीजीआरसी के सफल आयोजन की विस्तृत जानकारी भी दी।

मुख्यमंत्री के साथ हुई इस सौजन्य भेंट बैठक में मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, उद्योग विभाग की अपर मुख्य सचिव सुश्री ममता वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, सचिव डॉ. अजय कुमार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

अनजान लिंकों के जरिए केवाईसी जानकारी दर्ज न करें।

केवाईसी धोखाधड़ी से सावधान रहें!

अनजान लिंक = अनजान जोखिम

क्लिक करने से पहले सोचें

- फर्जी लिंकों से रहें सावधान।
- किसी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे भेजने वाले के बारे में पता करें।
- बैंक व्यक्तिगत जानकारी/ केवाईसी अपडेट के लिए कभी कोई लिंक नहीं भेजते।
- कभी भी ओटीपी, पिन, पासवर्ड, या गोपनीय जानकारी किसी को न बताएं।
- ऐसे मेसेजों को अनदेखा करें जिनमें दबाव की बनावटी परिस्थिति बताई गई हो।

सावधान रहें - सुरक्षित रहें
वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना तुरंत दें
cybercrime.gov.in पर या कॉल करें 1930 पर।

जागरूकता ही आपका सबसे मज़बूत रक्षा कवच है।

क्यूआर कोड स्कैन करें।
अधिक जानकारी के लिए देखें https://rbikehtahai.rbi.org.in
अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए rbikehtahai@rbi.org.in पर भेजें।
आधिकारिक व्हॉट्सऐप नं. 99990 41935 / 99309 91935

जनहित में जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

संपादकीय

किसानों की आशंकाएं

बीते शनिवार जारी किए गए भारत–अमेरिका व्यापार समझौते के प्रारूप ने एक बार फिर देश में उस बुनियादी सवाल को केंद्र में ला खड़ा किया है, जो हर मुक्त व्यापार समझौते के साथ उठता रहा है—इसकी कीमत आखिर कौन चुकाएगा और इसका वास्तविक लाभ किसे मिलेगा। कागज़ पर यह समझौते आर्थिक वृद्धि, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति मजबूत करने के वादे करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत में ये वादे अक्सर किसानों, छोटे उत्पादकों और कमजोर वर्गों की चिंताओं से टकराते दिखाई देते हैं। यही कारण है कि इस समझौते को लेकर उठ रही आशंकाएं केवल कुछ उत्पादों पर आयात शुल्क में छूट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे विश्वास, पारदर्शिता और भारतीय कृषि के भविष्य से गहराई से जुड़ी हुई हैं।

इन आशंकाओं की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ किसान संगठन आगामी 12 फरवरी को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह समझौता सोयाबीन तेल, सूखे अनाज और सेब जैसे उत्पादों तक ही सीमित खतरा नहीं पैदा करता, बल्कि इससे भारतीय किसानों की आय, बाजार में उनकी हिस्सेदारी और दीर्घकालिक सुरक्षा पर भी प्रश्नचिह्न लग सकता है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं और कृषि व दुग्ध उद्योग को समझौते में संरक्षित रखा गया है। निस्संदेह, सरकारी बयानों और दस्तावेज़ों में ये आश्वासन राहत देने वाले लगते हैं, लेकिन व्यवहार में किसानों की चिंताओं को केवल आश्वासनों से खारिज नहीं किया जा सकता।

पिछले अनुभव किसानों के अविश्वास को और गहरा करते हैं। यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड के साथ हुए पूर्व मुक्त व्यापार समझौतों का उदाहरण अक्सर दिया जा रहा है, जिनके बाद सस्ते आयात में भारी वृद्धि हुई और इसका सीधा असर घरेलू किसानों पर पड़ा। कम लागत पर विदेशों से आने वाले उत्पादों के सामने कमजोर भारतीय किसान टिक नहीं पाए और उनकी आय में गिरावट आई। यही डर अब अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते को लेकर भी सतह पर आ रहा है। विशेष रूप से सेब उत्पादकों के लिए यह चिंता और भी गंभीर है, क्योंकि अमेरिकी सेब को भारी सब्सिडी मिलती है और उसकी गुणवत्ता, पैकेजिंग व आपूर्ति श्रृंखला पहले से ही मजबूत मानी जाती है।

हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर और उत्तराखंड जैसे राज्यों के सेब उत्पादक लंबे समय से यह कह रहे हैं कि यदि अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क पचास प्रतिशत से घटाकर पच्चीस प्रतिशत कर दिया गया और न्यूनतम आयात मूल्य को पचास से बढ़ाकर अस्सी रुपये प्रति किलोग्राम किया गया, तो भी अमेरिकी सेब भारतीय प्रीमियम सेब की कीमत पर ही बाजार में उपलब्ध होगा। ऐसे में उपभोक्ता समान मूल्य पर अधिक आकर्षक और एकरूप गुणवत्ता वाले अमेरिकी सेब को तरजीह दे सकता है। इसका सीधा असर घरेलू सेब की मांग पर पड़ेगा। साथ ही, सेब का कोल्ड स्टोरेज में भंडारण पहले से ही महंगा सौदा है, और बाजार में कीमतों पर दबाव बढ़ने से यह पूरी तरह अलाभकारी हो सकता है। सरकार का पक्ष यह है कि समझौते में कृषि और दुग्ध उद्योग को संरक्षित रखा गया है और संवेदनशील क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। लेकिन संयुक्त समझौते के प्रारूप में कृषि और खाद्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्क कम करने और गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने की बात भी कही गई है। यही वह बिंदु है, जो किसानों की चिंता बढ़ाता है। कम आय, बढ़ती उत्पादन लागत और बढ़ते कर्ज के बोझ तले दबे किसानों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि किन उत्पादों पर, कितनी अवधि के लिए और किन शर्तों के साथ बाजार खोले जा रहे हैं। अस्पष्टता और अधूरी जानकारी के माहौल में आशंकाओं का बढ़ना स्वाभाविक है।

इसी कारण कई किसान संगठनों, विपक्षी दलों और कुछ राज्य सरकारों ने मांग की है कि इस समझौते का पूरा विवरण संसद के समक्ष रखा जाए और उस पर विस्तृत बहस हो। यह मांग किसी राजनीतिक विरोध से अधिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा से जुड़ी हुई है। मुक्त व्यापार समझौते केवल अंतरराष्ट्रीय कूटनीति या आर्थिक नीति का विषय नहीं होते, बल्कि वे घरेलू कानूनों की तरह ही करोड़ों लोगों की आजीविका को प्रभावित करते हैं। जब किसी कानून पर संसद में चर्चा आवश्यक मानी जाती है, तो ऐसे समझौतों पर पारदर्शिता और संसदीय निगरानी क्यों न हो, यह सवाल भी उतना ही जायज़ है।

एक किताब और फिल्म को लेकर हंगामे से उपजे प्रश्न

बीते सप्ताह नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा एक पूर्व सेनाध्यक्ष द्वारा लिखी गई किताब को लेकर उठाए सवालों पर बहस की अनुमति न मिलने से लोकसभा बार-बार स्थगित हुई। मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। दरअसल, लोकतंत्र में 'रणनीतिक मामलों' संबंधी सूचना को नियंत्रित करने की क्षमता महत्वपूर्ण है।

गत सप्ताह एक फिल्म और एक किताब देशभर में चर्चा के केंद्र में रही, 'घूसखोर पंडत' नामक फिल्म का शीर्षक बदलने और इससे जुड़ी तमाम प्रचार सामग्री हटाने पर नेटफ्लिक्स ने सहमति जताई है, इससे पहले कुछ नाराज़ लोगों ने 'जातिवादी' अपमान का विरोध किया, लखनऊ के हज़रतगंज पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से शिकायत की—प्रकरण के आखिर में बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने जीत की घोषणा करते हुए कहा, 'सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा'। भाटिया ने कहा, 'हम उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करने को प्रतिबद्ध हैं जो व्यावसायिक लाभ के लिए किसी भी जाति या समुदाय का अपमान करते हैं',और आगे कहा : 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है'। यह साफ़ नहीं कि बीजेपी नेता को क्या यह पता है कि ऐसा करते वक्त वे हास्य में निहित पहलू दबाने के अलावा व्यंग्य की मौत का जश्न भी मना रहे हैं। निश्चित ही, हास्यास्पद शीर्षकों का चलन हटा देना चाहिए। या शायद अब इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, खासकर तब जब आधा हफ्ता लोकसभा में बार-बार के स्थगन में निकल गया हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूर्व सेनाध्यक्ष, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा लिखी गई एक किताब को लेकर लगातार सवाल उठाने पर बज़िद रहे। सत्ताधारी बीजेपी भी उतनी ही दृढ़ता से अड़ी रही, किसी भी चर्चा की अनुमति देने से इनकार करते हुए यह तर्क दिया कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है और लिहाजा संसद में इस पर बहस नहीं की जा सकती।

जो चीज़ मौजूद नहीं, उस पर चर्चा संभव नहीं, ठीक? सिवाय इसके कि राहुल सदन के अंदर और बाहर प्रकाशन-पूर्व कॉपी लहराते रहे। हालांकि, इसकी पीडीएफ कॉपी पूरी दुनिया के पढ़ने के लिए उपलब्ध है। लेकिन सरकार भी सही है। किताब बाज़ार में उपलब्ध नहीं। रक्षा

मंत्रालय अभी भी जांच कर रहा है कि इसकी सामग्री सही है या नहीं।

जनरल नरवणे के आत्मकथात्मक विवरण में कुछ दिलचस्प बातें हैं। इनमें जून 2020 में लद्दाख के गलवान में भारत-चीन के बीच हुआ टकराव शामिल है - जब 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, और चार चीनी सैनिक भी मारे गए थे, हालांकि रूस की 'तास' जैसी विदेशी समाचार एजेंसियों का कहना था कि 45 चीनी मारे गए थे - साथ ही कुछ महीने बाद कैलाश श्रृंखला में हुई कार्रवाई का जिक्र भी है। किताब में भूटान के प्रभावशाली पूर्व राजा, जिग्मे सिंग्ये वांगचुक, जो के-4 नाम से लोकप्रिय हैं, उनके साथ हुई बातचीत; रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से आए संदेश; इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री के साथ बैठकों का जिक्र भी शामिल है।

देखा जाए तो, जिस पैराग्राफ ने राजनीतिक तूफान खड़ा किया है, वह लगभग हानिरहित है, और वास्तव में पूर्व सेना प्रमुख की कुछ पेसोपेश प्रस्तुत करता है - एक पैराग्राफ जिसे राहुल ने पकड़ रखा है। वह यह है कि जब चीनी सेना पीएलए के चार टैंक फिंगर-4 के पूर्व में कैलाश की चोटियों पर कब्जा जमा चुके भारतीय सैनिकों की ओर बढ़ रहे थे, तो जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री को फोन किया और उनसे पूछा कि अगली कार्रवाई पर मेरे लिए क्या आदेश है। इस पर राजनाथ सिंह ने, कथित तौर पर पीएम से बात करने के उपरांत, कुछ घंटों के बाद उन्हें वापस फोन किया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक साल से भी पहले किताब के प्रकाशक द्वारा भेजी प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से बताया है,नरवणे लिखते हैः'मैंने रक्षा मंत्री को स्थिति की गंभीरता बताई, जिन्होंने कहा कि वह मुझसे वापस संपर्क करेंगे, जो उन्होंने लगभग 22.30 बजे किया। उनका कहना था कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है और यह मामला पूरी तरह से एक सैन्य निर्णय है। 'जो उचित समझो, वो करो'। किसी सुस्पष्ट निर्णय की अनुपस्थिति में मुझे 'कोरा कागज़' पकड़ा दिया। खुली छूट के साथ, सारा दारोमदार मुझ पर छोड़ दिया गया। मैंने गहरी सांस ली और कुछ देर चुपचाप बैठा रहा'। सोचकर देखिए, क्या किसी प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री को अपने सेना प्रमुख से यही नहीं कहना चाहिए? वे सेनाध्यक्ष इसीलिए हैं कि ज़मीनी हकीकत का उन्हें सबसे अच्छी तरह पता हो, खासकर जब दुश्मन आगे बढ़ रहा हो, और इसलिए देशहित में जो बेहतरीन हो, उसे वही करना चाहिए।

हम सब जानते हैं कि जब राजनीति सैन्य मामलों में दखल देती है, तो क्या होता है, और इसके उलट का भी। भारत के पड़ोसी देश ढोंग करने वालों से भरे पड़े हैं, सैन्य और सिविलियन दोनों ही रूपों में। लेकिन हर कोई जानता है कि शक्तियों के बंटवारे में, जो लोकतंत्र की रीढ़ है, कुछ व्यावहारिक नियम दोनों पक्षों के लिए साफ-स्पष्ट होते हैं। राहुल गांधी का तर्क है कि जब से सरकार सत्ता में आई है, राष्ट्रीय सुरक्षा उसका मुख्य मुद्दा रहा और जब 2020 में लद्दाख में संकट आया, तो प्रधानमंत्री अपने सेनाध्यक्ष को सही सलाह नहीं दे पाए। निश्चित ही यह बहस का मुद्दा बनता है। यानि, गलवान में चीनी आपको क्यों पीछे धकेल पाए, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए? उस झड़प में कोर कमांडर ले.जन. हरिन्दर सिंह की क्या भूमिका थी? आर्मी कमांडर, ले. जन. वाईके जोशी (किताब में नाम 'जो') ने इसे कैसे संभाला? गलवान त्रासदी से क्या सबक सीखे? निश्चित ही राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा पवित्र मानकर बहस से परे रखा जाता है और संचालन विवरणों का सरेआम खुलासा नहीं किया जा सकता– रक्षा मंत्रालय ने किताब का प्रकाशन इसीलिए रोक रखा है। लेकिन अब यह रोक बेमानी हो गई क्योंकि किताब की पीडीएफ कॉपी बड़े पैमाने पर पढ़ी जा रही है। जो बात रक्षा मंत्रालय नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले, वह सबको मालूम है। और जो हमें इस छोटे से विवाद के सबसे महत्वपूर्ण सबक पर लाता है- जो निस्संदेह जल्दी ही किसी और मामले पर उठेगा- कि वह सारगर्भित शब्द, 'रणनीतिक मामला' जिसमें विदेश मामलों से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक शामिल है, उससे संबंधित सूचना नियंत्रण क्षमता का लोकतंत्र में बहुत महत्व है। जनता को कितना बताना है, के टेढ़े सवाल से हरेक सरकार जूझती है। लेकिन सनद रहे कि सूचना के इस युग में, डोनाल्ड ट्रम्प के 59वें दावे के बावजूद कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत-पाकिस्तान टकराव खत्म करवाया, जिसको लेकर वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंसी का पात्र बन चुके हैं, विश्वसनीय बने रहने की क्षमता ही महत्वपूर्ण है। कारगिल युद्ध, जिसे कभी-कभी 'मीडिया युद्ध' भी कहा जाता है, इसका एक बड़ा सबक था। दूसरी ओर, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड (लद्दाख में आमना-सामना) और ऑपरेशन सिंदूर, दोनों में एक अलग तरीका अपनाया गया, जो दुश्मन के सूचना चैनलों- वेबसाइटों, टीवी और वीडियो– द्वारा प्रसारित मिथ्या प्रचार को टक्कर देने और अपना प्रचार करने के मकसद से। जब संघर्ष जारी हो, शायद तब इसका औचित्य हो, लेकिन स्थिति सामान्य होने के बाद, यह उलट पड़ जाती है।

लोग उत्सुक होते हैं, खासकर जब वे 5,000 साल पुरानी सभ्यताओं से जुड़े हों, और खून-खराबे और सुलह, दोनों से जुड़ी उनकी अपनी ऐतिहासिक यादें हों। इसलिए जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जन. अनिल चौहान ने ऑपरेशन खत्म होने के कुछ ही हफ़्तों बाद टीवी पर स्वीकार किया था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में एक फाइटर जेट खोया,तो सवालों की झड़ी लग गई। कितने? कब? कैसे? असल में क्या हुआ था?

पुराने समय में, जब दुनिया शीत युद्ध की वजह से दो गुटों में बंटी थी, तत्कालीन पूर्वी गुट में एक शब्द था 'सामिज़्दत', जिसके तहत प्रतिद्वंद्वी गुट की सरकारों द्वारा प्रतिबंधित किसी भी अख़बार, गद्य अथवा कविता की हस्तलिखित नकल करके उनके लोगों तक पहुंचा दो। 'घूसखोर पंडत' और नरवणे की किताब दोनों इस श्रेणी में आते हैं। कभी-कभी आप सोचते होते होंगे कि क्या किताब की पीडीएफ उसी का आधुनिक प्रारूप है।

प्रेरणा

एक खोटा सिक्का और उज्ज्वल चरित्र की नींव

यह प्रसंग 1939 का है, जब भारत स्वतंत्रता से पहले के संघर्षशील दौर से गुजर रहा था और युवाओं के सामने भविष्य को लेकर अनिश्चितताएँ थीं। उसी समय आगरा के सेंट जॉन कॉलेज में अंग्रेज़ी साहित्य विषय से एम.ए. की पढ़ाई कर रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने एक मित्र के साथ साधारण-सा जीवन जी रहे थे। सीमित साधन, साधारण रहन-सहन और उच्च आदर्श—यही उनके दैनिक जीवन की पहचान थी। उस दौर की एक छोटी-सी घटना उनके व्यक्तित्व की गहराई, नैतिक दृढ़ता और आत्मिक संवेदनशीलता को उजागर करती है, जो आगे चलकर उनके सम्पूर्ण जीवन का मार्गदर्शक सिद्ध हुई।

एक दिन दीनदयाल जी अपने मित्र के साथ बाज़ार से दो पैसे की सब्ज़ी खरीदकर कमरे की ओर लौट रहे थे। चलते-चलते अचानक वे असहज हो गए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएँ उभर आईं और उनकी चाल भी धीमी पड़ गई। मित्र ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी जेब में एक-एक पैसे के कुल तीन सिक्के थे, जिनमें से एक सिक्का घिसा हुआ और खोटा था। सब्ज़ी खरीदते समय अनजाने में वही खोटा सिक्का सब्ज़ी बेचने वाली अम्मा को दे दिया गया। यह बात सुनने में मामूली लग सकती है, लेकिन दीनदयाल जी के मन में यह एक साधारण भूल नहीं थी। उनका अंतर्मन उन्हें बार-बार यह याद दिला रहा था कि अनजाने में ही सही, लेकिन किसी के साथ अन्याय हो गया है।

उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वे आगे बढ़ ही नहीं पाए। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि वापस बाज़ार जाना ही होगा। मित्र ने समझाने की कोशिश की कि यह तो अनजानी भूल है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और एक पैसे से किसी का बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन दीनदयाल जी के लिए प्रश्न पैसे का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और नैतिक शुद्धता का था। वे मानते थे कि सही और गलत का निर्णय इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कोई देख रहा है या नहीं, बल्कि इस आधार पर होना चाहिए कि अंतरात्मा क्या कहती है।

वे वापस उसी सब्ज़ी बेचने वाली मां के पास पहुँचे और पूरी बात सरलता से उनके सामने रख दी। उन्होंने बताया कि उनसे भूल हो गई है और वे खोटा सिक्का दे आए हैं। यह सुनकर उस मां ने मुस्कराते हुए बड़े अपनत्व से कहा कि बेटा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। जीवन में लाभ और हानि भाग्य से जुड़ी होती है। उसने दीनदयाल जी को माफ़ करते हुए कहा कि तुम्हारी भावना बहुत शुद्ध है, तुम जीवन में अवश्य आगे बढ़ोगे। उस मां के शब्दों में अपनापन था, आशीर्वाद था और जीवन का सहज दर्शन भी था। लेकिन दीनदयाल जी केवल क्षमा और आशीर्वाद लेकर लौटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने जेब से तीसरा खरा सिक्का निकाला और मां को दिया तथा बदले में अपना खोटा सिक्का वापस लिया। जब यह लेन-देन पूरा हुआ, तब उनके चेहरे पर जो संतोष झलका, वह किसी भी बाहरी पुरस्कार से कहीं अधिक मूल्यवान था। वह संतोष आत्मिक था, जो केवल तभी मिलता है जब व्यक्ति अपने भीतर के सत्य के साथ खड़ा होता है। उस क्षण उन्होंने स्वयं को हल्का, शांत और संतुलित महसूस किया।

यह घटना भले ही छोटी थी, लेकिन इसके भीतर एक बड़े जीवन का बीज छिपा हुआ था। यही वह मानसिकता थी जिसने आगे चलकर दीनदयाल उपाध्याय को एक विचारक, दार्शनिक और समाज का पथप्रदर्शक बनाया। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी सुविधा के लिए सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनके लिए नैतिकता कोई दिखावटी आचरण नहीं, बल्कि जीवन का स्वाभाविक प्रवाह थी। वे मानते थे कि यदि व्यक्ति छोटी-छोटी बातों में ईमानदार नहीं रह सकता, तो वह बड़े मंचों पर भी सच्चाई का दावा नहीं कर सकता।

आगे चलकर दीनदयाल जी ने राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की सेवा और राष्ट्र निर्माण का साधन माना। उन्होंने अपने चिंतन के माध्यम से 'एकात्म मानववाद' का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को एक-दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक-दूसरे का पूरक माना गया। उनके विचारों की जड़ें इसी प्रकार की नैतिक घटनाओं में थीं, जहाँ व्यक्ति अपने लाभ से ऊपर उठकर कर्तव्य और सत्य को प्राथमिकता देता है।

सन 1967 में उन्हें भारतीय जनसंघ का अखिल भारतीय अध्यक्ष चुना गया। यह पद उनके लिए सम्मान के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारी भी था। उन्होंने संगठन और कार्यकर्ताओं को यह सिखाया कि राजनीति में सफलता का पैमाना केवल पद या सत्ता नहीं, बल्कि चरित्र और निष्ठा होनी चाहिए। उनका पूरा जीवन इस बात का उदाहरण रहा कि विचार और व्यवहार में कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने निजी जीवन में ईमानदार है, वही सार्वजनिक जीवन में भी विश्वास के योग्य होता है।

आज के समय में, जब अक्सर नैतिक मूल्यों को व्यवहारिकता के नाम पर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है, दीनदयाल जी का यह प्रसंग हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें याद दिलाता है कि चरित्र का निर्माण बड़े भाषणों से नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के छोटे-छोटे निर्णयों से होता है। एक खोटा सिक्का लौटाने का साहस वही साहस है, जो आगे चलकर अन्याय, भ्रष्टाचार और अनैतिकता के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति देता है।

अंततः यह कथा केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक जीवंत संदेश है। यह बताती है कि सच्ची प्रगति बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता से जन्म लेती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि जब व्यक्ति अपने भीतर की आवाज़ को सर्वोच्च मान लेता है, तो वही आवाज़ उसे जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाती है। एक खोटे सिक्के से शुरू हुई यह यात्रा अंततः राष्ट्र के चिंतन और चरित्र को दिशा देने वाली बन गई, और यही नैतिकता का सच्चा आदर्श है।

वैश्विक आकर्षण का केंद्र बनता भारत, आर्थिक और ढांचागत सुधारों की गति बढ़ानी होगी

हाल में भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया। टैरिफ में यह बड़ी कमी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है। इस समझौते से जहां कई क्षेत्रों में भारत से अमेरिका को निर्यात बढ़ेगा, वहीं भारत में अमेरिकी निवेश में भी वृद्धि होगी। साथ ही दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई दिशा मिलेगी। वैश्विक कंपनियां चीन के विकल्प के रूप में भारत में निवेश बढ़ाएंगी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ेगा। इससे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बनने की दिशा में और तेजी से बढ़ेगा। गत दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा भी कि अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ हुए व्यापार समझौते भारत की बढ़ती आर्थिक अहमियत के प्रतीक हैं। नई वैश्विक व्यवस्था भारत की ओर झुकती दिखाई दे रही है। पहले कहा जाता था कि भारत अवसर गंवा देता है, लेकिन अब दुनिया का मानना है कि यदि वे तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़े, तो महत्वपूर्ण अवसर खो देंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत का तेज आर्थिक विकास और महंगाई पर नियंत्रण एक दुर्लभ संयोजन है। मजबूत बुनियादी ढांचा, विशाल घरेलू बाजार, मध्यवर्ग की बढ़ती क्रयशक्ति, एमएसएमई की गति, ऊर्जा विकास, युवा शक्ति, डिजिटल प्रगति तथा मैन्यूफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र की ताकत ने भारत को दुनिया के लिए आकर्षक बना दिया है। इसी कारण विकसित देश भारत से द्विपक्षीय और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) कर रहे हैं। भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क के अनुसार भारत मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, इथेनाल, तंबाकू, कुछ सब्जियों और मांस जैसे संवेदनशील कृषि एवं डेरी उत्पादों के मामले में पूरी तरह सुरक्षित है। यह समझौता भारत के टेक्सटाइल एवं परिधान, चमड़ा एवं फुटवियर, प्लास्टिक एवं रबर उत्पाद, आर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प और चुनिंदा मशीनरी जैसे क्षेत्रों को अमेरिकी बाजार में बड़े अवसर देगा। इसके अलावा जेनेरिक दवाओं, रत्न-हीरे और एयरक्राफ्ट पाट्र्स सहित कई उत्पादों के निर्यात को गति मिलेगी। विशेष रूप से एमएसएमई, किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डालर के अमेरिकी बाजार के द्वार खुलेंगे। निर्यात बढ़ने से महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार बढ़ेंगे। इस समझौते के तहत भारत अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों की बड़ी श्रृंखला पर टैरिफ घटाएगा या समाप्त करेगा तथा अगले पांच वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डालर के ऊर्जा उत्पाद, एयरक्राफ्ट एवं पाट्र्स, कीमती धातुएं, टेक्नोलाजी उत्पाद और कोकिंग कोल खरीदने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

अमेरिका भारत के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बाजार है। वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच 131.84 अरब डालर का व्यापार हुआ, जिसमें भारत का निर्यात 86.51 अरब डालर और आयात 45.33 अरब डालर रहा। वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से दिसंबर के बीच भारत ने अमेरिका को 65.88 अरब डालर का निर्यात किया। 18 प्रतिशत टैरिफ भारत को चीन-प्लस-वन रणनीति के स्वाभाविक विकल्प के रूप में और मजबूत करता है। वर्तमान में अमेरिका ने ब्राजील पर 50 प्रतिशत, चीन पर 34 प्रतिशत, वियतनाम और बांग्लादेश पर 20 प्रतिशत तथा मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और थाइलैंड पर 19 प्रतिशत टैरिफ लगाया हुआ है। ऐसे में भारत-अमेरिका समझौता वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा।

पिछले दिनों हुआ भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इससे दो अरब लोगों का साझा बाजार बनेगा, जो वैश्विक जीडीपी के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करेगा। बीते वर्ष ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ हुए एफटीए का इस साल कार्यान्वयन महत्वपूर्ण होगा। साथ ही मारीशस, यूएई, आस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नार्वे और लिकटेंस्टाइन) के साथ लागू एफटीए के लाभ भी बढ़ेंगे। इस वर्ष पेरू, चिली, आसियान, मेक्सिको, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इजरायल और गल्फ कंट्रीज काउंसिल सहित अन्य देशों के साथ नए एफटीए हो सकते हैं।

इन समझौतों का पूरा लाभ उठाने के लिए भारत को आर्थिक सुधारों और घरेलू ढांचागत बदलावों की गति बढ़ानी होगी। नियमों और नियामक संस्थाओं के कामकाज में सुधार, कर सुधारों को गहराई देना और जीएसटी को अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक है। घरेलू कंपनियों को गुणवत्ता, तकनीक और कुशल मानव संसाधन पर ध्यान देना होगा। साथ ही प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, गैर-टैरिफ बाधाएं कम करने, सेवा क्षेत्र का लाभ उठाने, निर्यात विविधीकरण, कृषि सुरक्षा तथा पर्यावरण और श्रम मानकों के पालन पर विशेष ध्यान देना होगा।

उम्मीद है भारत-अमेरिका शीघ्र ही व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इससे 2030 तक दोनों के बीच 500 अरब डालर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। यह समझौता भारत के निर्यात और रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित हो सकता है तथा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अभियान

काशी विश्वनाथ की अलौकिक पुकार: जहाँ हर श्वास में शिव हैं

काशी केवल एक शहर नहीं है, यह एक जीवित चेतना है, एक ऐसी अनुभूति जो मनुष्य के भीतर उतरकर उसे बदल देती है। कहा जाता है कि संसार में यदि कहीं समय रुक जाता है, तो वह काशी है। यहाँ भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ बहते हैं—गंगा की अविरल धारा की तरह। इसी काशी के हृदय में विराजमान हैं बाबा विश्वनाथ, जिनके दर्शन मात्र से जन्म-जन्मांतर के संस्कार जाग उठते हैं। जब कोई भक्त वाराणसी जाने का संकल्प करता है, तो वह केवल यात्रा नहीं करता, बल्कि आत्मा की एक गहन तीर्थयात्रा पर निकल पड़ता है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर की ओर बढ़ते हुए गलियों का संकरापन मन को विचलित नहीं करता, बल्कि भीतर की भीड़ को शांत करता है। इन गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है मानो हर दीवार, हर मोड़, हर सीढ़ी शिवकथा कह रही हो। कहीं से शंखनाद की ध्वनि आती है, कहीं "हर हर महादेव" का जयघोष सुनाई देता है, तो कहीं चाय की दुकान पर बैठा कोई वृद्ध काशी की महिमा सुनाता मिलता है। यह सब मिलकर एक ऐसा वातावरण रचते हैं, जहाँ भक्त अनायास ही स्वयं को शिव के चरणों में समर्पित कर देता है।

काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर मान्यता है कि यह स्वयंभू है। यहाँ शिव किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि चेतना के रूप में विराजते हैं। यही कारण है कि यहाँ दर्शन केवल आँखों से नहीं होते, बल्कि मन और आत्मा से होते हैं। जैसे ही भक्त मंदिर परिसर में प्रवेश करता है, उसकी सांसें स्वतः ही गहरी होने लगती हैं, हृदय में एक अजीब-सी शांति उतर आती है। यह शांति किसी उपदेश से नहीं, बल्कि अनुभूति से आती है।

मंदिर में प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच और कतारें आधुनिक व्यवस्था का हिस्सा हैं, लेकिन भक्त के लिए यह भी एक प्रकार की तपस्या ही है। लंबी कतार में खड़े होकर, धैर्य के साथ आगे बढ़ते हुए, मन में केवल एक ही भाव रहता है—"बस एक झलक मिल जाए।" यही प्रतीक्षा, यही उत्कंठा दर्शन को और भी पावन बना देती है। जब गर्भगृह के भीतर शिवलिंग के दर्शन होते हैं, तो वह क्षण शब्दों से परे होता है। आँखें भर आती हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, और मन बस इतना ही कह पाता है—"नाथ, सब तुम्हीं हो।"

काशी में दर्शन का समय भी अपने आप में एक आध्यात्मिक लय लिए होता है। भोर

की बेला में, जब मंदिर के कपाट खुलते हैं और पहली आरती होती है, तब वातावरण में ऐसी दिव्यता घुल जाती है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। दीपों की लौ, मंत्रों की गूंज और घंटियों की ध्वनि मिलकर ऐसा लगता है मानो साक्षात कैलाश उतर आया हो। वहीं संध्या के समय, जब गंगा के तट पर आरती होती है और आकाश में दीपों की रोशनी झिलमिलाती है, तब मनुष्य स्वयं को ब्रह्मांड का एक छोटा-सा अंश मानने लगता है।

गंगा स्नान और बाबा के दर्शन का संबंध काशी की आत्मा से जुड़ा है। माना जाता है कि गंगा में स्नान कर, शुद्ध मन से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने से पापों का नाश होता है। लेकिन इससे भी बढ़कर, यह प्रक्रिया मनुष्य को अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। गंगा के ठंडे जल में डुबकी लगाते समय जैसे सारे अहंकार, सारी थकान धुल जाती है। और फिर उसी शुद्धता के साथ बाबा के सामने खड़ा होना, जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण बन जाता है।

काशी की यात्रा केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहती। यहाँ के घाट इस यात्रा को और भी गहरा अर्थ देते हैं। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में जब सैकड़ों दीप एक साथ जलते हैं, तो लगता है मानो स्वयं देवता इस दृश्य को देखने उतर आए हों। अस्सी घाट की सुबह, जहाँ उगते सूर्य के साथ भजन और योग होता है, मन को नई ऊर्जा से भर देती है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट, जहाँ चिताएँ निरंतर जलती रहती हैं, जीवन और मृत्यु के सत्य को बिना किसी लाग-लपेट के सामने रख देते हैं। यहाँ खड़े होकर मनुष्य समझ पाता है कि अंत में कुछ भी साथ नहीं जाता, सिवाय कर्म और भक्ति के।

काल भैरव और संकट मोचन जैसे मंदिर काशी की यात्रा को पूर्णता प्रदान करते हैं। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है और मान्यता है कि उनकी अनुमति के बिना काशी में कोई नहीं रह सकता। वहीं संकट मोचन में हनुमान जी के दर्शन भक्त को साहस और विश्वास से भर देते हैं। ये सभी स्थल मिलकर काशी को एक ऐसा आध्यात्मिक वृत्त बनाते हैं, जहाँ हर दिशा से शिव ही शिव दिखाई देते हैं।

काशी विश्वनाथ धाम की यात्रा वास्तव में नियमों और समय-सारिणी से कहीं अधिक है। यह एक आंतरिक अनुशासन सिखाती है—पवित्रता का, संयम का और समर्पण का। मंदिर में प्रवेश से पहले मन और शरीर की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, क्योंकि शिव केवल बाहरी नहीं, आंतरिक शुद्धता के भी प्रतीक हैं। यहाँ आकर यह स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति दिखावे का विषय नहीं, बल्कि एक मौन संवाद है भक्त और भगवान के बीच।

अंततः, जब कोई भक्त काशी से लौटता है, तो वह वही व्यक्ति नहीं रहता जो यहाँ आया था। उसके भीतर कुछ बदल चुका होता है। शायद दृष्टि थोड़ी और विनम्र हो जाती है, शायद जीवन की आपाधापी थोड़ी कम लगने लगती है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन मनुष्य को यह सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी संसार से परे कैसे रहा जाए। काशी इसी का नाम है—जीवन और मोक्ष के बीच का सेतु।

जो भी काशी आता है, वह जान जाता है कि यहाँ आना उसका चुनाव नहीं था, बल्कि बाबा का बुलावा था। और एक बार यह बुलावा सुन लिया जाए, तो जीवन भर उसकी गूंज हृदय में बनी रहती है—हर हर महादेव।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

शहरी विकास वर्ष में गुजरात बना टिकाऊ शहरी आयोजन तथा विकास का मॉडल

- 'कैच द रेन' पहल अंतर्गत वर्षा जल संग्रह क्षमता में 4.19 लाख किलोलीटर की वृद्धि हुई
- महानगर पालिका तथा नगर पालिका क्षेत्रों में 90 लाख पेड़-पौधे लगाए गए, शहरी क्षेत्रों में 240 हेक्टेयर से अधिक नए ग्रीन स्पेस विकसित किए जाएंगे
- राज्य में शहरी स्वच्छता तथा कूड़ा प्रबंधन के लिए 2,756 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 1,823 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी

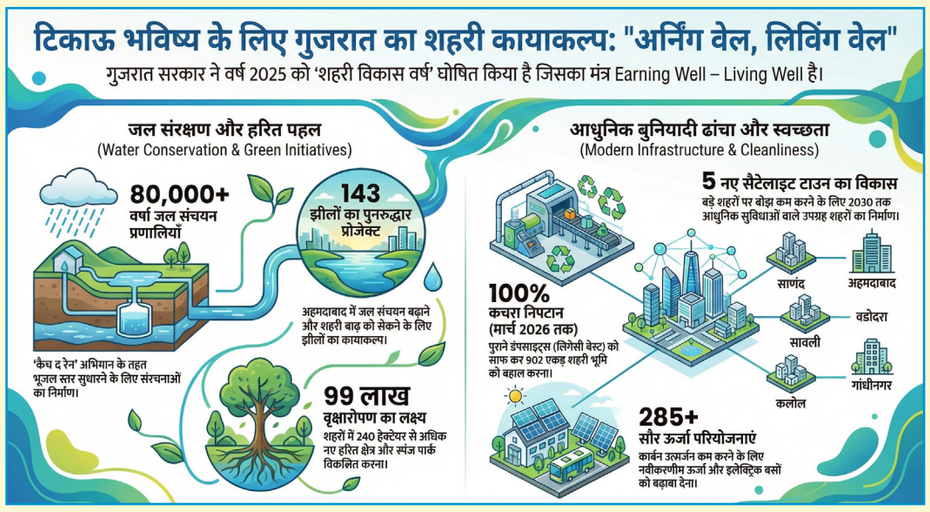

जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात सरकार ने 'अर्निंग वेल, लिविंग वेल' संकल्प अंतर्गत गुजरात के शहरों को श्रेष्ठ सुविधायुक्त बनाने तथा नागरिकों को उच्च गुणवत्तायुक्त जीवन प्रदान करने के उद्देश्य के साथ वर्ष 2025 को 'शहरी विकास वर्ष' घोषित किया है। शहरी विकास वर्ष 2025 अंतर्गत राज्य सरकार का टिकाऊ शहरी आयोजन तथा विकास का लक्ष्य है। शहरी विकास वर्ष के दौरान राज्य सरकार बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण शुरू कर नए ग्रीन स्पेस के निर्माण एवं 100 प्रतिशत लिगेसी वेस्ट की निकासी के लिए प्रतिबद्ध है।

शहरी क्षेत्रों में 240 हेक्टेयर से अधिक नए ग्रीन स्पेस बनाए जाएंगे

गुजरात ने हमेशा टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन दिया है, जिसके हिस्से के रूप में राज्य के शहरी क्षेत्रों में ग्रीन कवर बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। शहरी विकास वर्ष के दौरान राज्य के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में 240 हेक्टेयर से अधिक नए ग्रीन स्पेस विकसित किए जाएंगे; जिनमें बाग-बगीचे, वर्षा जल को भूमि में उतारने तथा भूमिगत जल रिचार्ज करने के लिए स्पंज पार्क्स एवं अर्बन फॉरेस्ट आदि शामिल हैं। हाल में इसके लिए विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में है। शहरी विकास वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा कुल 340 से अधिक परियोजनाएँ पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 146 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।

कैच द रेन : वर्षा जल संग्रह क्षमता में 4.19 लाख किलोलीटर की वृद्धि

गुजरात सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रह की क्षमता बढ़ाने के लिए कैच द रेन पहल शुरू की है। इसके अंतर्गत राज्य के 17 महानगर पालिका क्षेत्रों तथा 152 नगर पालिका क्षेत्रों में कुल लगभग 2,900 रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित किए गए हैं; जिसके कारण शहरों में वर्षा जल का संग्रह करने की क्षमता में लगभग 4.19 लाख किलोलीटर की वृद्धि हुई है। इसके अलावा; 2,603 परियोजनाएँ हाल में कार्यान्वित हैं, तो 1,230 परियोजनाएँ निविदा के चरण में हैं तथा 6,642 नई परियोजनाएँ आयोजनाधीन हैं। इसके साथ ही; तालाबों के रीडेवलपमेंट एवं पुनर्स्थापना पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। शहरी विकास वर्ष 2025 अंतर्गत कुल 140 लेकफ्रंट प्रोजेक्ट्स का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; जिनमें 54 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, 57 चल रहे हैं, 9 निविदा चरण में हैं और 20 प्रोजेक्ट आयोजनाधीन हैं।

राज्य में टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न परियोजनाएँ

राज्य सरकार ने टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यभर में 285 से अधिक सौर परियोजनाएँ (सोलर प्रोजेक्ट्स) शुरू करने का लक्ष्य रखा है, जिससे शहरों में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाकर कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त; मलिन जल के पुनरुपयोग के लिए 20 रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वॉटर (आरटीडब्लूडब्लू) प्रोजेक्ट्स कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जिसमें दैनिक अनुमानित 656 मिलियन लीटर पानी पुनः उपयोग के लिए उपलब्ध बनेगा। इसी प्रकार; शहरी प्रदूषण के विरुद्ध वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए शहरी विकास विभाग का राज्य की सभी महानगर पालिकाओं को समाविष्ट करने वाले 'क्लीन एयर एक्शन प्लान्स' को लॉन्च करने का लक्ष्य है। राज्य की शेष चार बड़ी महानगर पालिकाओं भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ तथा गांधीनगर के लिए भी क्लीन एयर एक्शन प्लान तैयार किया गया है।

महानगर पालिका तथा नगर पालिका क्षेत्रों में 90 लाख पेड़-पौधों का रोपण पूर्ण

इसके अतिरिक्त; शहरी विकास वर्ष के दौरान राज्य के शहरों को हरियाला बनाने की दिशा में 99 लाख पेड़-पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 17 महानगर पालिका क्षेत्रों तथा 152 नगर पालिका क्षेत्रों में लगभग 90 लाख पेड़-पौधों का रोपण किया गया है।

मार्च 2026 तक राज्य के शहरों में 100 प्रतिशत लिगेसी वेस्ट की निकासी का लक्ष्य

उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार शहरों में वर्षों से पड़े कूड़े-कचरे की वैज्ञानिक निकासी द्वारा पर्यावरण सुरक्षा, जन स्वास्थ्य तथा शहरी विकास को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने मार्च 2026 तक राज्य के शहरों में 100 प्रतिशत लिगेसी वेस्ट की निकासी का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में कुल 304.09 लाख मैट्रिक टन लिगेसी वेस्ट चिह्नित किया गया है; जिसमें से अब तक 281.802 लाख मैट्रिक टन कूड़े की वैज्ञानिक तरीके से निकासी की गई है। इसके अतिरिक्त; शहरी स्वच्छता एवं कूड़ा प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए 2,756 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 1,823 से अधिक परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा। राज्यभर में शहरों के सार्वजनिक स्थलों से गंदगी तथा अस्वच्छता को दूर करने के लिए 1,533 गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स (जीवीपी) की पहचान कर उसकी निकासी का लक्ष्य रखा गया है। टिकाऊ शहरी आयोजन एवं विकास को प्रोत्साहन देने वाली यह प्रत्येक पहल विकसित गुजरात से विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

राज्यव्यापी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक और मील का पत्थर

गांधीनगर में एलन मस्क की स्पेसएक्स की सब्सिडियरी स्टारलिंक तथा गुजरात सरकार के बीच आपसी सहयोग के आशय पत्र (एलओआई) का मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में विनिमय

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए डिजिटल भारत के संकल्प को साकार करते हुए गुजरात में डिजिटल कनेक्टिविटी मिशन तथा स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स को सुदृढ़ करने की नई दिशा मिलेगी
- मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री की दिसंबर-2025 में स्टारलिंक ऑपरेशन स्पेसएक्स की वाइस प्रेसिडेंट सुश्री लॉरेन ड्रेयर के साथ आयोजित प्रारंभिक बैठक की फलश्रुति
- राज्यव्यापी मॉडर्न डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीमलेस कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन होगा

पायलट इनिशिएटिव्स अंतर्गत

- राज्य में कम टेलीकॉम नेटवर्क तथा कनेक्टिविटी की समस्या वाले सुदूरवर्ती एवं आदिजाति क्षेत्रों को ई-गवर्नेंस फैसिलिटी तथा कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़कर सरकार की सेवाओं को तेजी तथा सरलता से पहुँचाने का आयोजन
- एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट सहित ट्राइबल क्षेत्रों में रिलायेबल डिजिटल सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, विद्यालयों तथा राज्यव्यापी टेली-मेडिसीन सेंटर्स को स्मार्ट कनेक्टिविटी से जोड़कर सुदृढ़ व त्वरित स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएँ उपलब्ध कराने का आयोजन
- सरकारी एजेंसियों, विद्यालयों तथा आपदा प्रबंधन टीम की कैपिसिटी बिल्डिंग की जाएगी
- सरकारी विद्यालयों, पोर्ट फैसिलिटीज, वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी तथा सभी जिलों के आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष को जोड़ा जाएगा

जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत@2047 के विजन को साकार करने में सुदृढ़ डिजिटल गवर्नेंस को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बताया है। उनके द्वारा दिए गए डिजिटल भारत के संकल्प को गुजरात के ग्रामीण सुदूरवर्ती स्थलों सहित राज्यव्यापी विस्तृत करने की दिशा में गुजरात सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सोमवार को इस उद्देश्य से एलन मस्क की स्पेसएक्स की सब्सिडियरी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ आपसी सहयोग के आशय पत्र (एलओआई) का विनिमय किया।

इस एलओआई के परिणामस्वरूप राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी मिशन तथा रणनीतिक पहलों से सुदूरवर्ती, दूरदराजी तथा कम टेलीकॉम सुविधा और नेटवर्क की समस्या वाले क्षेत्रों में हाईस्पीड सैटेलाइट आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी।

इस एलओआई अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट में कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी), ई-गवर्नेंस सुविधाओं, सरकारी विद्यालयों, जिला आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष, पोर्ट्स, वन्यजीव अभयारण्यों के क्षेत्रों को जोड़ने का आयोजन है।

यह एलओआई नर्मदा तथा दाहोद जैसे आकांक्षी जिलों सहित राज्य के आदिजाति जिलों में डिजिटल इन्क्लूजन (समावेशन) के लिए महत्वपूर्ण कदम बनेगा। इस एलओआई के क्रियान्वयन से इन जिलों में पुलिस आउटपोस्ट्स, आपदा प्रबंधन केन्द्रों, वन्यजीव मॉनिटरिंग तथा कृषि अनुसंधान केन्द्रों के लिए मजबूत कनेक्टिविटी द्वारा सिक्योरिटी तथा स्टेबिलिटी बढ़ने के साथ रिलायेबल डिजिटल सर्विस डिलीवरी भी सुनिश्चित होगी। इस पहल अंतर्गत राज्य के स्कूलों में शिक्षा के लिए स्मार्ट कनेक्टिविटी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में स्वास्थ्य सुख-सुविधा की सेवाएँ और टेली-मेडिसीन सुविधाएँ आसानी से एवं तेजी से उपलब्ध होंगी। साथ ही साथ; विभिन्न सरकारी एजेंसियों, विभागों, विद्यालयों और डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम्स की कैपिसिटी बिल्डिंग के लिए भविष्य में संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य में सीमलेस तथा ईजी कनेक्टिविटी की आवश्यकताओं के संदर्भ में इस एलओआई के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार तथा स्टारलिंक के प्रतिनिधियों के संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की प्रेरक उपस्थिति में सोमवार को गांधीनगर में यह एलओआई विनिमय समारोह आयोजित किया गया। राज्य सरकार की ओर से उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप तथा स्टारलिंक की ओर से स्टारलिंक इंडिया के हेड श्री प्रभाकर जयकुमार ने इस एलओआई का परस्पर आदान-प्रदान किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस संयुक्त प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन आगामी भविष्य में राज्य की डिजिटल सेवाओं को अधिक व्यापक बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होगा और ई-गवर्नेंस की प्रगति को अधिक गति देगा।

इस एलओआई में राज्य के जीआईडीसी के इंडस्ट्रियल पार्क्स, हाईवे सेफ्टी सिस्टम्स, मैरीटाइम पोर्ट कनेक्टिविटी तथा कोस्टल पुलिस ऑपरेशन में भी कनेक्टिविटी अधिक मजबूत बनाने के विषयों को शामिल किया गया है। गुजरात सरकार तथा एलन मस्क की स्पेसएक्स की सब्सिडियरी स्टारलिंक के बीच आपसी सहयोग के एलओआई विनिमय समारोह में मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, उद्योग विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ममता वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव श्रीमती पी. भारती, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. अजय कुमार तथा राज्य सरकार एवं स्टारलिंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

कच्छ को बड़ी रेल सौगात: गांधीधाम–आदिपुर चौहरीकरण व 'वाई' कनेक्टिविटी कार्य पूर्ण, रेल संरक्षा आयुक्त ने किया ट्रॉली निरीक्षण

जीएनएस)। अहमदाबाद मंडल अपने रेल नेटवर्क को अधिक सक्षम, सुरक्षित तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में गुजरात के गांधीधाम–आदिपुर रेलखंड के बीच चौहरीकरण तथा आदिपुर स्टेशन पर 'वाई' कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। इस खंड का 9 फरवरी 2026 को श्री ई. श्रीनिवास, रेल संरक्षा आयुक्त (CRS), पश्चिम सर्कल द्वारा ट्रॉली निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण टीम में मंडल रेल प्रबंधक अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) श्री प्रदीप गुप्ता, मुख्य ट्रैक इंजीनियर, मुख्य परिचालन प्रबंधक (जी) तथा निर्माण एवं ओपन लाइन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

इस परियोजना के अंतर्गत 17 किमी ट्रैक लिंकिंग, 8 छोटे पुलों का निर्माण तथा 2.60 लाख घन मीटर अर्थवर्क किया गया है। आदिपुर स्टेशन पर सिग्नल एवं दूरसंचार (S&T) तथा ऑपरेटिंग कंट्रोल बिल्डिंग का निर्माण किया गया है और चौथी लाइन सहित पूरे सेक्शन का विद्युतीकरण पूर्ण हुआ है। गोपालपुर स्टेशन को आधुनिक स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। गांधीधाम बी केबिन में 16 नए प्वाइंट्स एवं क्रॉसिंग तथा आदिपुर स्टेशन पर 21 नए प्वाइंट्स एवं क्रॉसिंग के साथ 1 लूप लाइन सहित प्रमुख यार्ड रीमॉडलिंग कार्य किए गए हैं।

गांधीधाम–आदिपुर ब्रॉडगेज रेलखंड कांडला एवं मुंद्रा बंदरगाहों सहित भुज, वायोर और अन्य क्षेत्रों को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण माल ढुलाई मार्ग है। वर्तमान में यह खंड अत्यधिक व्यस्त रहने से परिचालन पर दबाव बना रहता है, जिसे कम करने के लिए दो अतिरिक्त लाइनों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस मार्ग से नमक एवं सामान्य माल की भी बड़े पैमाने पर ढुलाई होती है और मुंद्रा बंदरगाह की बढ़ती क्षमता को देखते हुए भविष्य में यातायात और बढ़ने की संभावना है।

यह खंड अहमदाबाद मंडल का सर्वाधिक GMT (Gross Million Tonnes) लोडिंग वाला सेक्शन है, जहाँ से प्रतिवर्ष 70 से अधिक GMT लोडिंग होती है। चौहरीकरण से लाइन क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे ट्रेनों का संचालन अधिक सुरक्षित, समयनिष्ठ एवं सुचारु बनेगा। इससे यात्री ट्रेनों की समयपालनता में सुधार होगा, पीक समय में परिचालन आसान होगा तथा नई ट्रेनों या अतिरिक्त फेरों की संभावनाएँ बढ़ेंगी।

गोपालपुर नए स्टेशन के निर्माण से अहमदाबाद की ओर से आने वाली गाड़ियों को भुज जाने के लिए गांधीधाम में इंजन रिवर्सल की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे लगभग 20-25 मिनट की समय बचत होगी। आदिपुर स्टेशन पर 'वाई' कनेक्टिविटी उपलब्ध होने से ट्रेनों को दिशा परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, जिससे समय एवं ईंधन दोनों की बचत होगी और परिचालन सरल बनेगा।

इस परियोजना से कांडला एवं मुंद्रा बंदरगाहों से जुड़े कंटेनर, पेट्रोलियम, उर्वरक, खाद्यान्न एवं अन्य माल के परिवहन में तेजी आएगी। मालगाड़ियों का टर्नअराउंड समय कम होगा, वैगनों का बेहतर उपयोग संभव होगा तथा लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, जिससे उद्योगों और व्यापार को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही यह परियोजना कच्छ क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति देने, व्यापार, पर्यटन एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा निवेश के अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

गांधीधाम–आदिपुर चौहरीकरण एवं 'वाई' कनेक्टिविटी परियोजना क्षेत्रीय विकास और सुदृढ़ रेल अवसंरचना की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो कच्छ क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

---

10 फरवरी : विश्व दलहन दिवस

चने की उत्पादकता में गुजरात देश में अग्रसर, अरहर उत्पादन में भी श्रेष्ठ प्रदर्शन

- 2021-22 से 2023-24 के दौरान अरहर की औसत उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 1199 किलोग्राम तथा चने की औसत उत्पादकता 1795 किलोग्राम दर्ज हुई
- अप्रैल-नवंबर, 2025-26 के दौरान गुजरात ने लगभग 69.98 मिलियन डॉलर के 74,652 मैट्रिक टन दलहन का निर्यात किया
- दलहन का बुवाई क्षेत्र 6.62 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 10.89 लाख हेक्टेयर हुआ, तो उत्पादन 6.79 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 15.51 लाख मैट्रिक टन तक पहुँचा
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'दलहन आत्मनिर्भर मिशन' से गुजरात में दलहन की खेती में उल्लेखनीय वृद्धि हुई

जीएनएस)। गांधीनगर : दलहन की खेती, उत्पादकता तथा उसके समर्थन मूल्य को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विश्वभर में 10 फरवरी को 'विश्व दलहन दिवस' मनाया जाता है। विश्व में दलहन के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता तथा आयातक देश के रूप में भारत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'दलहन आत्मनिर्भर मिशन' शुरू किया है; जो पोषण सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की ओर एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने इस मिशन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अरहर तथा चना जैसे दलहनों की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्ध दर्ज कराई है।

अरहर तथा चना उत्पादकता में गुजरात की प्रगति, दलहन निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि

गुजरात में अरहर तथा चने की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। 2021-22 से 2023-24 के दौरान अरहर की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 1199 किलोग्राम तथा चने की उत्पादकता 1795 किलोग्राम दर्ज हुई थी, जबकि 2023-24 में 1714 किलोग्राम चना उत्पादकता के साथ राज्य

ने प्रथम स्थान हासिल किया।

उल्लेखनीय है कि गुजरात विभिन्न प्रकार के दलहनों की खेती करता है; जिनमें चना, मूंग, उड़द, मोठ, अरहर तथा मटर शामिल हैं। राज्य इन दलहनों का निर्यात भी करता है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा) के अनुसार अप्रैल से नवंबर (2025-26) के दौरान गुजरात ने वैश्विक बाजारों में 69.98 मिलियन डॉलर (लगभग 581 करोड़ रुपए) मूल्य के 74,652.82 मैट्रिक टन दहलन का निर्यात किया।

'दलहन आत्मनिर्भर मिशन' से गुजरात में दलहन की खेती में उल्लेखनीय वृद्धि हुई

भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन से प्रेरित होकर गुजरात में पिछले पाँच वर्षों के दौरान दलहन की खेती में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। दलहन का कुल बुवाई क्षेत्र 2018-19 में 6.62 लाख हेक्टेयर था, जो 2023-24 में बढ़कर 10.89 लाख हेक्टेयर हुआ है। इसी प्रकार; दलहन का उत्पादन भी लगभग तीन गुना बढ़ा है। 2018-19 में दलहन उत्पादन 6.79 लाख मैट्रिक टन था, जो 2023-24 में बढ़कर 15.51 लाख मैट्रिक टन हुआ है। इनमें चना, मूंग, मोठ तथा उड़द की खेती में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विशेषकर; चने की बुवाई में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली है; जिसमें 2018-19 में 1.73 लाख हेक्टेयर का बुवाई क्षेत्र 2023-24 में बढ़कर 6.22 लाख हेक्टेयर हुआ है, जबकि उत्पादन 2.35 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 10.66 लाख मैट्रिक टन हुआ है।

भारत सरकार का दलहन में आत्मनिर्भरता का मिशन चना, अरहर एवं उड़द की खेती को प्रोत्साहन दे रहा है। मिशन अंतर्गत किसानों को प्रमाणित बीज व सब्सिडी के साथ खेत सम्बद्ध प्रदर्शनियों तथा उत्पादकता में सुधार के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त; अधिक अच्छी उपज के लिए राज्य सरकार ने बीज प्रतिस्थापन दर (एसआरआर) योजना लागू की है, जो यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को गुणवत्तायुक्त प्रमाणित बीज मिले।

आधुनिक कृषि पद्धतियों द्वारा उत्पादकता को प्रोत्साहन

कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसान अधिक से अधिक आधुनिक कृषि पद्धतियाँ अपना रहे हैं। मशीनीकरण, उन्नत संकर (हाइब्रिड) किस्मों, प्रमाणित बीज, कीटनाशकों तथा उर्वरकों का ड्रोन आधारित छिड़काव और बीज को मजबूत बनाने की तकनीकों द्वारा उपज में वृद्धि हो रही है। टपक सिंचाई तथा छिड़काव जैसी सिंचाई पद्धतियों, ऑर्गेनिक खादों तथा मिश्र एवं अंतरफसल खेती से संसाधनों के उपयोग में सुधार हो रहा है। थ्रेशर, कम्बाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर तथा ग्रेडर जैसे उपकरणों से खेती का कामकाज आसान हुआ है, मजदूरी घटी है और कार्यक्षमता बढ़ी है। एकीकृत, प्राकृतिक एवं जैविक खेती से दलहन उत्पादन में भी वृद्धि हुई है।

पश्चिम रेलवे
सुधार कार्य
डिविजनल रेलवे मैनेजर (WA), पश्चिम रेलवे, 6th फ्लोर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मुंबई सेंट्रल, मुंबई - 400 008. टेंडर नोटिस मंगा रहे हैं। काम और जगह: मुंबई सेंट्रल - मूविंग एरिया की सतह और ड्रेनेज में सुधार। काम की अनुमानित लागत: ₹ 4,31,46,919.19 EMD:₹ 3,65,700/- BCT/25-26/313 ता.: 03.02.2026 जमा करने की तारीख और समय: ता.: 27.02.2026 को 15.00 बजे तक। खुलने की तारीख और समय: 27.02.2026 को 15.30 बजे। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं। 1093
हमें लाईक करें: X.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे
रखरखाव कार्य
सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (सब), पश्चिम रेलवे, मुंबई सेंट्रल ई-टेंडर नंबर: W R - MMCTOESUB (ESPT)/19/2025 आमंत्रित करते हैं। काम का नाम: मुंबई उपनगरीय सेक्शन के चर्चगेट विरार के बीच PSI सिस्टम में 110/25KV AC उपकरणों की सालाना शेड्यूल मेंटेनेंस एक्टिविटी और सभी TRD उपकरणों की थर्मो विजन चेकिंग। काम की अनुमानित लागत: रु. 2,13,56,350/- बिड सिक्योरिटी: रु. 2,56,800/- जमा करने की तारीख और समय: ता. 02.03.2026 को 15:00 बजे तक। खोलने की तारीख और समय: ता. 02.03.2026 को 15:30 बजे। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट: www.ireps.gov.in पर जाएं। 1091
हमें फॉलो करें: X.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे - रतलाम मंडल
ई-निविदा सूचना
वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर, कर्षण वितरण, रतलाम मंडल, पश्चिम रेलवे भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु IREPS पोर्टल के माध्यम से खुली निविदाएं आमंत्रित करते हैं: **निविदा क्रमांक: EL/TRD/58/2025-26/22, दिनांक 06.02.2026. कार्य का नाम:** TRD Work in connection with electrification work between Chanderiya (CNA)- Ajmer (All). **अनुमानित लागत:** रु. 5,65,37,300/-. **बयाना राशि:** रु.4,32,700/- **समापन अवधि:** 12 Months. **निविदा दस्तावेज़ की राशि:** Nil. **ऑनलाइन बिडिंग बंद होने की दिनांक एवं समय:** 02.03.2026 at 15:00 hrs. **ऑफर की वैधता:** 60 days from the date of opening. **वेबसाइट: www.ireps.gov.in. नोटिस बोर्ड:** वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर, कर्षण वितरण, रतलाम मंडल, पश्चिम रेलवे के कार्यालय के प्रवेश द्वार के सामने। SPAN/13/1/450
हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे
रद्दीकरण सूचना
टेंडर नंबर: BCT/25-26/307 तारीख: 29/01/2026 DOP: 24/02/2026 को तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया है। 1104
हमें फॉलो करें: X.com/WesternRly

भावनगर मंडल के सतर्क लोको पायलट ने 10 सिंहों के झुंड को ट्रेन की चपेट में आने से बचाया

जीएनएस)। भावनगर रेलवे मंडल द्वारा सिंहों/वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। मंडल के निर्देशानुसार ट्रेनों का संचालन करने वाले लोको पायलट निर्धारित गति का पालन करते हुए विशेष सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। भावनगर मंडल के लोको पायलटों की सतर्कता एवं वन विभाग के फॉरेस्ट ट्रैकरों के समन्वय से पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 159 सिंहों की जान बचाई जा चुकी है। वहीं, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 101 सिंहों को सुरक्षित बचाया गया है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 09 फरवरी, 2026 (सोमवार) को लोको पायलट श्री रामावतार मीना, मुख्यालय-जूनागढ़ तथा सहायक लोको पायलट

श्री सोनू शर्मा, मुख्यालय-जूनागढ़ ने सासणगीर–कांसियानेश सेक्शन में किलोमीटर संख्या 117/03–117/01 के बीच रेलवे ट्रैक पर अचानक 10 सिंहों के झुंड को देखा। तत्पश्चात उन्होंने ट्रेन संख्या 52955 वेरावल–जूनागढ़ यात्री गाड़ी को तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर सुरक्षित रूप से रोक लिया।

लोको पायलट द्वारा ट्रेन मैनेजर (गार्ड) श्री संजय दिक्षित, मुख्यालय-जूनागढ़ को तुरंत सूचना दी गई। वन विभाग के फॉरेस्ट ट्रैकर श्री जे. जी. परमार ट्रेन में हीं मौजूद थे। उनके द्वारा सभी सिंहों को सुरक्षित रूप से रेलवे ट्रैक से हटाया गया। स्थिति सामान्य पाए जाने के उपरांत लोको पायलट को ट्रेन के प्रस्थान की अनुमति दी गई, जिसके बाद ट्रेन को सावधानीपूर्वक गंतव्य की ओर रवाना किया गया।

इस घटना की जानकारी प्राप्त होने पर लोको पायलटों द्वारा किए गए इस सराहनीय एवं संवेदनशील कार्य के लिए मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमाँशु शर्मा एवं अन्य अधिकारियों द्वारा प्रशंसा व्यक्त की गई।

आधुनिक कृषि पद्धतियों द्वारा उत्पादकता को प्रोत्साहन

जीएनएस)। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसान अधिक से अधिक आधुनिक कृषि पद्धतियाँ अपना रहे हैं। मशीनीकरण, उन्नत संकर (हाइब्रिड) किस्मों, प्रमाणित बीज, कीटनाशकों तथा उर्वरकों का ड्रोन आधारित छिड़काव और बीज को मजबूत बनाने की तकनीकों द्वारा उपज में वृद्धि हो रही है। टपक सिंचाई तथा छिड़काव जैसी सिंचाई पद्धतियों, ऑर्गेनिक खादों तथा मिश्र एवं अंतरफसल खेती से संसाधनों के उपयोग में सुधार हो रहा है। थ्रेशर, कम्बाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर तथा ग्रेडर जैसे उपकरणों से खेती का कामकाज आसान हुआ है, मजदूरी घटी है और कार्यक्षमता बढ़ी है। एकीकृत, प्राकृतिक एवं जैविक खेती से दलहन उत्पादन में भी वृद्धि हुई है।

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने अहमदाबाद मंडल के 5 कर्मचारियों को संरक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक (प्रभारी) श्री प्रदीप कुमार ने पश्चिम रेलवे मुख्यालय, मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में अहमदाबाद मंडल के 5 कर्मचारियों को रेल संरक्षा में उत्कृष्ट कार्य, सतर्कता और सुरक्षित ट्रेन संचालन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए "मैन ऑफ द मंथ" (दिसंबर–2025) संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया। इन कर्मचारियों की सजगता से संभावित दुर्घटनाएँ टलीं और रेल संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हुई।

सम्मानित कर्मचारियों का विवरण:

1. श्री अनिल कुमार, फिटर-III (C&W), भीलड़ी: 11 दिसंबर 2025 को ड्यूटी के दौरान रोलिंग इन परीक्षण करते समय उन्होंने एक कोच का एयर स्प्रिंग दबा हुआ पाया। जांच में एयर प्रेशर न होना और कॉक बंद होना पाया गया। उन्होंने तुरंत उसे सही किया, लीकेज जांची और गाड़ी को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाने के लिए C&W स्टाफ द्वारा एस्कॉर्ट की व्यवस्था करवाई तथा कंट्रोल को सूचना दी।

2. श्री ग्रैश कुमार डी., लोको पायलट, अहमदाबाद: 8 दिसंबर 2025 को ट्रेन संख्या 19223 चलाते समय खोडियार स्टेशन के पास ट्रैक पर भारी लोहे का क्लैम्प लगा देखा। उन्होंने तुरंत ट्रेन रोकी। सहायक लोको पायलट ने क्लैम्प हटाया। जांच के बाद ट्रेन को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ाया गया। उनकी सतर्कता से एक बड़ी दुर्घटना टली।

3. श्री साजीद अहमद, पॉइंट्समैन, अहमदाबाद: 12 दिसंबर 2025 को एक मालगाड़ी गुजरते समय उन्होंने एक वैगन के ब्रेक शू में आग और चिंगारी देखी। उन्होंने तुरंत लाल सिग्नल दिखाकर गाड़ी रुकवाई। स्टेशन स्टाफ की मदद से आग बुझाई गई और आवश्यक कार्रवाई के बाद गाड़ी रवाना हुई।

4. श्री रवि कुमार मीना, गेटमैन, जसाली: 17 दिसंबर 2025 को उन्होंने गुजरती गाड़ी के एक वैगन में चिंगारी देखी और तुरंत सूचना दी। जांच में हॉट एक्सल पाया गया। सहायता इंजन मंगवाकर सुरक्षित तरीके से गाड़ी को स्टेशन लाया गया और सिक वैगन अलग किया गया। उनकी सतर्कता सराहनीय रही।

5. श्री दीपक यादव, स्टेशन मास्टर, भद्रेश्वर रोड: 18 दिसंबर 2025 को रन-थ्रू गाड़ी का निरीक्षण करते समय उन्होंने एक वैगन से चिंगारी और गंध महसूस की। उन्होंने तुरंत कंट्रोल और अगले स्टेशन को सूचना दी। जांच में ब्रेक ब्लॉक जाम पाया गया। वैगन को अलग कर सुरक्षित संचालन सुनिश्चित किया गया।

सोना वायदा में 1349 रुपये और चांदी वायदा में 3949 रुपये की वृद्धि: क्रूड ऑयल वायदा में 31 रुपये की नरमी

जीएनएस)। मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 137101.54 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 27828.72 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 109271.88 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 39026 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3027.2 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 22286.46 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 156000 रुपये के भाव पर खूलकर, 158500 रुपये के दिन के उच्च और 155546 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 155451 रुपये के पिछले बंद के सामने 1349 रुपये या 0.87 फीसदी की बढ़त के साथ 156800 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 1204 रुपये या 0.94 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 128921 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 137 रुपये या 0.86 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 16085 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी मार्च वायदा 154825 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 157000 रुपये और नीचे में 154224 रुपये पर पहुंचकर, 1052 रुपये या 0.68 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 154983 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 158634 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 160000 रुपये और नीचे में 158000 रुपये पर पहुंचकर, 157335 रुपये के पिछले बंद के सामने 1011 रुपये या 0.64 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 158346 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 259887 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 264885 रुपये और नीचे में 251544 रुपये पर पहुंचकर, 249892 रुपये के पिछले बंद के सामने 3949 रुपये या 1.58 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 253841 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 4382 रुपये या 1.7 फीसदी की बढ़त के साथ 262195 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 4577 रुपये या 1.77 फीसदी की तेजी के संग 262481 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

कमोडिटी वायदाओं में 27828.72 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 109271.88 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 22286.46 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 39026 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 3439.07 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 1.15 रुपये या 0.09 फीसदी औंधकर 1241.7 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 2.9 रुपये या 0.89 फीसदी औंधकर 322.75 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 2 रुपये या 0.64 फीसदी औंधकर 310.2 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 1.2 रुपये या 0.63 फीसदी औंधकर 188.65 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 1983.79 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा 5750 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5801 रुपये और नीचे में 5682 रुपये पर पहुंचकर, 31 रुपये या 0.53 फीसदी औंधकर 5793 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 31 रुपये या 0.53 फीसदी की गिरावट के साथ 5795 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 315 रुपये के भाव पर खूलकर, 315 रुपये के दिन के उच्च और 287.7 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 320.2 रुपये के पिछले बंद के सामने 31.2 रुपये या 9.74 फीसदी गिरकर 289 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 30.6 रुपये या 9.57 फीसदी औंधकर 289.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा 975 रुपये पर खूलकर, 8.7 रुपये या 0.89 फीसदी घटकर 969 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 11939.02 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 10347.44 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2863.97 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 239.29 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 18.75 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 314.85 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 820.29 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1154.55 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 3.22 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.07 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9257 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 61619 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 31949 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 416975 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 51818 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 8986 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 20152 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 62545 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17281 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 18894 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा 38658 पॉइंट पर खूलकर, 39300 के उच्च और 38658 के नीचले स्तर को छूकर, 1493 पॉइंट बढ़कर 39026 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 33.3 रुपये की गिरावट के साथ 240.9 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 18.1 रुपये की गिरावट के साथ 20.4 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 180000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 566 रुपये की गिरावट के साथ 1153 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 440000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 932 रुपये की गिरावट के साथ 1004 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 6.73 रुपये की गिरावट के साथ 19.65 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 340 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.3 रुपये की गिरावट के साथ 2.32 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 80 पैसे के सुधार के साथ 152.8 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 290 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 10.6 रुपये की बढ़त के साथ 24.75 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 1009 रुपये की गिरावट के साथ 1466 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2142 रुपये की गिरावट के साथ 3939 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 4.42 रुपये की गिरावट के साथ 21.04 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.33 रुपये की गिरावट के साथ 6.99 रुपये हुआ।

सत्यमेव जयते
गुजरात सरकार

Gujarat Tourism

भक्ति, संस्कृति और प्रकृति का अनूठा संगम!

भवनाथ महादेव के दिव्य सानिध्य में आयोजित महाशिवरात्रि के मेले में मृगीकुंड के शाही स्नान और मध्य रात्रि को निकलने वाली पवित्र नागा साधुओं की शोभायात्रा का साक्षी बनना बहुत ही सौभाग्य का अवसर है। आइए, हर-हर महादेव के ओजस्वी नाद के साथ इस ऐतिहासिक मेले में पधारें और भक्ति के रंग में रंग जाएँ।

मुख्य आकर्षण

11 फरवरी, 2026
- ध्वजारोहण कार्यक्रम
- महाआरती
- डमरू यात्रा

11 से 14 फरवरी, 2026
- पवित्र नागा साधुओं के पवित्र अग्नि कुंड
- भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम
- अविरत चलने वाले अन्नक्षेत्र

15 फरवरी, 2026
- पवित्र नागा साधुओं के दिव्य शोभायात्रा का दर्शन

"गिरनार की गोद में भवनाथ महादेव के सानिध्य में आयोजित यह मेला लोक-उत्सव के साथ-साथ गुजरात की आध्यात्मिक चेतना और सनातन आस्था का भी गुंजन है।" - **श्री हर्ष संघवी,** माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात